



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बिल्व का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर हाउस में बिल्व का पौधा लगाया

दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने रिफाइनरी के काम में तेजी लाने की बात कही

नई दिल्ली/जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बिल्व का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल्व जैसे पौधे धार्मिक और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तथा विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज सम्पत्तियों की सूची बनवाई गई है तथा उनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।**

बीकानेर हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हमारी सरकार राजस्थान के चर्हुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान रिफाइनरी

के काम में तीव्रता लाकर यहां बनने वाले बाय-प्रोडक्ट्स को संसाधित करके इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम

किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से धार्मिक अंब पेपरलीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट को भेज दिया गया।

यह राशि गंगापुरसिटी थाना पुलिस ने साल 2021-22 में अलग-अलग आरोपियों से बरामद की थी। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि गंगापुर सिटी थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके जब्तशुदा एक करोड़ 20 लाख दो हजार रूपए व सामान को न्यायालय में जमा करवाने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर नकदी को एकडी में जमा करवाने का आदेश दिया, वहीं जब्तशुदा सामान एसओजी थाने को सौंप दिया।

कोर्ट ने कहा कि एकडी अधिक ब्याज देने वाले बैंक में करवाई जाए और बैंक का नाम विशिष्ट लोक अभियोजक को बताया जाए।

सुनवाई के दौरान रीट पेपरलीक मामले के आरोपी चन्दनराम, कमला विश्‍नोई, सुमन, सोहिनी महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह, राजेश कुमार मीना, संजय कुमार मीना बत्ती लाल मीणा, रवि मीणा, अमित कुमार मीणा, कमलेश मीणा, शिवदान मीना, नरेन्द्र विश्‍नोई, मुन्नीलाल विश्‍नोई व अशोक कुमार मौजूद रहे, जबकि शेष आरोपियों का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अब 11 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

■ **हल्के वाहनों का आवागमन चालू रखा गया है तथा बढ्रीनाथ यात्री भी फिलहाल जारी है।**

है। छोटे वाहनों टैक्सी, कार सहित अन्य हल्के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बढ्रीनाथ यात्रा फिलहाल जारी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देते हुए रविवार को बताया फिलहाल बढ्रीनाथ हाईवे यहाँ पर हल्के वाहनों के ही खोला गया है।

पांडुकेनवर से ऊपर सभी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है।

गडकरी के घर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुलिस और डॉंग स्कॉयड की टीम ने गडकरी के घर मेंसर्व ऑपरेशन भी चलाया।

कुछ घंटों बाद गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश विष्णु राउत है। उमेश विष्णु राउत मेडिकल चौक स्थित एक देसी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार किया है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में ही मौजूद हैं। पुलिस की टीम अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर धमकी देने के पीछे की संशा को जानना चाहेगी कि कहीं इस घटना में कोई और एंगल तो नहीं है।

सरकार ने 35 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिक वसूली गई राशि को वसूलना शामिल होगा। एनपीपीए ने साफ किया है कि निर्धारित मूल्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, जिसे लागू होने पर जोड़ा जा सकता है। निर्माताओं को सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म वी में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी और एनपीपीए तथा राज्य औषधि नियंत्रकों को जानकारी देनी होगी। स्पेसिफाइड फॉर्मूलेशन और निर्माताओं के लिए जारी किए गए किसी भी पूर्व मूल्य आदेश को इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है

रायपुर, 03 अगस्त। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को आशंका है कि उन्हें शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और न्यायालय सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए विचार कर सकता है।

बघेल ने याचिका में मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्रष्टे के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है

■ **शराब, कोयला तथा महादेव सट्टा घोटाले में सीबीआई और ईडी की जाँच के बाद उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य व केन्द्र की जाँच एजेंसियों ने कुछ समय पूर्व संबंधित मामलों की जाँच की गति तेज कर दी है।**

कि, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। यह राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।

सितंबर से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 12 के अनुसार हर साल रजिस्टर्ड पोस्ट की संख्या में गिरावट आ रही है। साल 2011-12 में रजिस्टर्ड डाक से भेजने वाले आर्टिकल 24 करोड़ से घटकर 2019-20 में 18 करोड़ के रह गए। 25 फीसदी की कमी साफ देखी जा सकती है। कोरोना के बाद से तो स्थिति और खराब हो गई है।

‘योगी के कैबिनेट मंत्री राजभर बिहार में भाजपा पर दबाव बना रहे हैं’

वे बिहार विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों पर गठबंधन करना चाहते हैं

लखनऊ, 3 अगस्त। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब नए समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके संकेत उस समय मिलने शुरू हो गए जब उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो सारे विकल्प खुले हुए हैं।

दरअसल, भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए गैर-भाजपा दलों के साथ तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत

■ **राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी कई वर्षों से बिहार में सक्रिय है, इसलिए वे विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।**

देकर अपनी राजनीतिक ताकत फिर से दिखानी शुरू कर दी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा अगर बिहार में भाजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं होता है, तो हम सभी विकल्प खुले रखेंगे।

योगी सरकार में मंत्री राजभर ने

कहा कि उनकी पार्टी प्रवेश किशोर की जन सुराज पार्टी और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सहित कई छोटी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है।

राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम से कम 156 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा यह

सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या और कैसी बनती है। हम बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जहां हम पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं।

भाजपा के सूत्रों ने बताया कि राजभर सीवान, चंपारण, सारण, गोपालगंज और बक्सर के कुछ इलाकों में सम्मानजनक सीटों के लिए भाजपा से कड़ी मोलभाव कर रहे हैं जहां राजभर, राजवंशी, राजघोषी और भर समुदायों की अच्छी-खासी मौजूदगी है। पार्टी का लक्ष्य पटवा और मंडल जैसी जातियों को भी एकजुट करना है।

एयर इंडिया का पुनः “राष्ट्रीयकरण” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विमान ऑर्डर दिया है, तकनीक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश किया है, और ब्रांड की साख वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बदलाव, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी, कई सालों में होता है, महीनों में नहीं।

आज जो समस्याएँ एयर इंडिया में देखी जा रही हैं, वे पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि व्यवस्था की विफलता। अभी अगर फिर से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो भारत के आर्थिक सुधारों की साख को बड़ा झटका लगेगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा, जिन्हें नीति में स्थिरता चाहिए।

यह बात सही है कि एयर इंडिया के साथ भावनात्मक लगाव आज भी बना हुआ है। दशकों तक यह भारत की हवाई

■ **पर, यह भी जरूरी है कि एयर इंडिया का मैनेजमेंट अपनी दिक्कतों व कमियों के बारे में सही जानकारी दे जनता को, नहीं तो यह “इम्पेशन” जोर पकड़ लेगा कि मैनेजमेंट के पास सिविल एविएशन का पूरा अनुभव नहीं है और कार्य कुशलता के अभाव में कंपनी डूब जायेगी।**

पहचान रह गई, प्रधानमंत्रियों को ले जाने वाली, संकेत में नागरिकों को वापस लाने वाली और प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने वाली एयरलाइन। जब वही एयरलाइन निजी हाथों में संघर्ष करती दिखती है, तो लोगों को पीड़ा होती है।

अगर टाटा समूह द्वारा दी जा रही पूंजी और स्वतंत्रता के बावजूद एयरलाइन लगातार विफल होती है, तो सार्वजनिक हित की बात फिर से उठ सकती है। मनीष तिवारी की यह चिंता, कि गैर-विमानन पेशेवर (नॉन

एविएशन प्रॉफेशनल्स) ऐसे चला रहे हैं, इस बड़े भय को दर्शाती है कि एयर इंडिया की आत्मा सिर्फ लाभ कमाने के चक्कर में कहीं खो रही है।

इसके अलावा, भारत जैसे विशाल देश में हवाई संयुक्त एक रणनीतिक संसाधन है। अगर निजी नियंत्रण में कुछ प्रमुख मार्ग घाटे का सौदा बनते हैं, तो जनता की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में सरकार को सीधे या रैग्युलेशन के जरिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

फिर भी, एयर इंडिया का पुनः राष्ट्रीयकरण अभी जलदबाजी होगी और

मुश्किल से हो रहे सुधारों को कमजोर करने का खतरा पैदा हो सकता है। एयर इंडिया को कब्जे में लेने की नहीं, बल्कि कड़ी निगरानी की जरूरत है। सरकार को अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, टाटा समूह को संवाद बेहतर करना होगा, तेजी से कदम उठाने होंगे और यात्रियों व नीति-निर्माताओं, दोनों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे इस जिम्मेदारी के लायक हैं।

निजीकरण कभी कोई जादू की छड़ी नहीं था। यह एक ऐसा कदम था, जिससे सरकार को एयरलाइन चलाने के काम से आज़ाद किया जा सके, ताकि वह शासन पर ध्यान दे सके। इसी भावना में, जरूरी है कि जो टूटा है, उसे ठीक किया जाए, बिना उसे फिर से पूरी तरह बिगाड़े।